Media Coverage of Fly Ash Brick Initiatives of DA



निर्माण उद्योग फ्लाई-ऐश ईंटों से पर्यावरण अनुकूल बनने की ओर अग्रसर

पटना। बिहार भारत में सबसे तेजी से बढते राज्यों में से एक है। 2005-06 से 2014-15 की अवधि के दौरान, स्थिर कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी सालाना 10.5 प्रतिशत पर बढ़ा, जो सभी प्रमुख भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। बिहार में ईट उधोग एक महत्वपूर्ण झेत्र है। वर्तमान में ईंट उधोग विकेन्द्रीकृत उत्पादन गतिविधि पर आधारित है तथा ऊर्जा गहन, संसाधन घटाने और अत्यधिक प्रदूषण वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। हाल ही में, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बीएसपीसीबी के अध्यक्ष डॉ अशोक घोष ने पारंपरिक ईंट बनाने के तरीकों के कारण शीर्ष मिट्टी के नकसान की चिंता भी उठाई। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज समूह के वाईस प्रेसिडेंट, डॉ सौमेन माईटी के अनुसार, आज की स्थिति में, बिहार में फ्लाई-ऐश ईंटों के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने से, थर्मल पावर प्लांट्स के कचरे के उत्पादक उपयोग का तथा उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का अवसर है। साथ ही साथ स्थानीय समदाय को रोजगार प्रदान करता है । बिहार के चयनित जिलों में लाग फ्लाई-एश ईंट गुणवत्ता रेटिंग प्रणाली ने दिखाया है कि फ्लाई ऐश ईंट निमार्ता भारतीय मानक के अनुसार अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटें बता रहे हैं।

साष्ट्रीय समर्पण

शीर्ष मिट्टी खोने से कृषि उत्पादन में आएगी बाधा

पटना (एसएनबी)। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बिहार में पारंपरिक ईंट बनाने की प्रथाओं के कारण शीर्ष मिट्टी के नुकसान पर अपनी चिंता व्यक्त की है। इससे जुड़ी हुई विभिन्न चुनौतियों पर काम करने के लिए

डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज, एक गैर-लाभकारी संठन के साथ मिलकर सक्रिय प्रयास कर रहा है। बिहार में ईट उद्योग, ऊर्जा गहन, संसाधन घटाने और अल्यधिक प्रदूषण

प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विकेन्द्रीत उत्पादन गतिविधि पर आधारित है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष ने पारंपरिक ईंट बनाने के तरीकों और बिहार की अर्थव्यवस्था पर इसका समग्र प्रभाव होने के कारण शीर्ष मिट्टी के नुकसान की चिंता उठाई है। उन्होंने जोर दिया कि बिहार मुख्य रूप से कृषि राज्य है। ईंट उत्पादन और सड़क

निर्माण के कारण हर साल 10,000 हेक्टेयर शीर्ष मिट्टी खो जाती है। नतीजतन कृषि उत्पादन में काफी हद तक बाधा आ जाएगी। राज्य की खाद्य उत्पादन क्षमता को चुनौती देगी। लाल ईट उद्योग में खाद्य सुरक्षा, वायु

ईंट उत्पादन व सड़क निर्माण में शीर्ष मिट्टी के जाया होने पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जतायी चिंता

की लागत पर नहीं है। पर्यावरण अनुकूल ईंट उत्पादन प्रौद्योगिकियों और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पहल करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस संबंध में व्यवस्थित कार्रवाई और फॉलो-अप करने के मामले में बिहार अग्रणी रहा है। डॉ. के. विजया लक्ष्मी, उपाध्यक्ष, डेवलपमेंट अल्टरनेटिंज ने कहा कि फ्लाई ऐश ईंटें सबसे अधिक अनुकूल सामग्री है।



ईंट उद्योग को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए पहल

पटना। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने बिहार में पारंपरिक ईट बनाने की प्रथाओं के कारण शीर्ष मिटटी के नुकसान पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इससे जुडी हुई विभिन्न चुनौतियों पर काम करने के लिए डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज संगठन के साथ मिलकर सिक्रय प्रयास कर रहा है। बीएसपीसीबी के अध्यक्ष डॉ. अशोक घोष ने पारंपरिक ईट बनाने के तरीकों और बिहार की अर्थव्यवस्था पर इसका समग्र प्रभाव होने के कारण शीर्ष मिट्टी के नुकसान की चिंता उठाई है। उन्होंने जोर दिया कि बिहार मुख्य रूप से कृषि राज्य है और ईट उत्पादन और सड़क निर्माण के कारण हर साल 10000 हेक्टेयर शीर्ष मिट्टी खो जाती है। नतीजतन कृषि उत्पादन में काफी हद तक बाधा आ जाएगी और राज्य की खाद्य उत्पादन क्षमता को चुनौती देगी। वहीं डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज समूह के वाईस प्रेसिडेंट, डॉ. सौमेन माईटी के अनुसार बिहार में 153 फ्लाई ऐश ईट उद्यम हैं। उन्होंने संकेत दिया कि नीति पर्यावरण बिहार में अनुकूल है, लेकिन कार्यान्वयन को आगे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है।



मिक्की दे रहीं पर्यावरण अनुकूल उद्योग को बढ़ावा

हौसले को सलामः अररिया की महिला उद्यमी ने ईंट उद्योग के नियमों को फिर से किया परिभाषित

पटना, संवाददाता

बिहार में ईट उद्योग हमेशा से पुरुषों के प्रभत्व वाला क्षेत्र रहा है तथा महिलाओं की भागीदारी केवल परंपरागत ईट निर्माण इकाइवों में मजदरों के रूप में रही है। परन्तु, अपनी मेहनत और कार्यकुशलता से इस स्थिति को बदलने में कामयाब रही हैं, वह महिला हैं अरिया की-श्रीमती मिक्की देवी। जिन्होंने इस उद्योग के नियमों को फिर से परिभाषित किया और अब एक सफल उद्यमी है, जो अरिया जिले के नारपतांज इलाके में एक फ्लाई-ऐश ईट बनाने की इकाई चलाती है। वह वास्तव में बिहार में फ्लाई ऐश ईट सेक्टर में पहली महिला उंघमियों में से एक है। अरिया जिले के मध्य दक्षिण की पूर्व मुखिया श्रीमती मिक्की देवी काफी समय से व्यवसाय शुरू करने के विचार को रखे हुए थी और फ्लाई-एश ईट निर्माण के क्षेत्र में एक



अवसर उनको दिखा। उन्होंने अररिया में मध्रा दक्षिण के वर्तमान मुखिया से उनके समर्थन के लिए परामर्श किया और भवानी शंकर पलाई ऐश ईटों की स्थापना की और इसका संचालन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। उद्यम को सरकारी ऋण से जुड़ी सब्सिडी का लाभ भी मिला, जो की प्रधानमंत्री रोजगार के माध्यम से पीएमईजीपी से प्राप्त हुआ। बकौल मिक्की देवी, जब मैंने पीएमईजीपी योजना के लिए आवेदन किया था, मैंने इंटरनेट पर फ्लाई ऐश ईट निर्माण पर व्यापक शोध किया। शोध ने मुझे फ्लाई ऐश ईंट निर्माण, मशीनरी और उपकरणों

की आवश्यकता में शामिल प्रक्रियाओं को समझने में मदद की ं विपणन को अपने आप देखती है। और कहां से मैं उन्हें स्रोत कर सकती थी यही जानकारी मिली। जब सरकार ने पीएमईजीपी योजना के तहत मुझे ऋण मंजूर किया, तो योजना पूरी तरह से तैयार की गई। इकाई में विनिर्माण और संचालन अप्रैल 2018 में शुरू हुआ और महीने के अंत तक उनकी पहली फ्लाई ऐश ईटों को बेचा गया। 15 जुलाई, 2018 तक यूनिट द्वारा निर्मित और बेची गई ईटों की कुल संख्या 3 लाख थी, जिनमें से 70 से 75 प्रतिशत ईंटें एरिया में निजी परिवारों को और बाकी को सरकारी परियोजनाओं को आपूर्ति की गई थी। बाजार की मांग और उत्पादन लागत के आधार पर प्रत्येक ईट 6.5 से 7.5 पर बेची जाती है। उनकी इकाई को कहलगांव में एनटीपीसी इकाई से फ्लाई ऐश मिलती है। वह आपूर्तिकर्ताओं से कच्चे माल की

खरीद और अंतिम उत्पादों के वर्तमान में इकाई की प्रति दिन 10.000 ईटों का निर्माण करने की क्षमता है। फ्लाई ऐश विनिर्माण इकाई में वर्तमान में 16 कर्मचारी हैं, जिनमें से 8 स्थायी कुशल कर्मचारी हैं और शेष को सामयिक रूप से किराए पर लिया जाता है। हालांकि, मिक्की देवी के लिए यात्रा आसान नहीं थी, जैसा कि स्थापना के शुरूआती दो महीनों के दौरान उन्होंने अपने उत्पाद की कीमत पर ज्ञान की कमी के कारण व्यापार में घाटे को देखा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुशसित आकार के विपरीत हम जिन मोल्डों का उपयोग कर रहे थे. वे बडे आकार के थे। इसके अलावा फ्लाई ऐश ईट, बाजार में एक नया उत्पाद होने के कारण प्रचार करना मुश्किल था और कभी-कभी, मांग की कमी या कच्चे माल की आपूर्ति की कमी के कारण भी उत्पादन बंद हो गया।

MORNING INDIA

Bihar poised for greening of construction sector through fly-ash technology

OUR CORRESPONDENT

PATNA: Bihar is one of the fastest growing states in India. During the period 2005-06 to 2014-15, the **Gross State Domestic Product** (GSDP) of Bihar at constant prices grew annually at 10.5 percent, which is one of the highest among all major Indian states. Amongst many sectors in Bihar, the brick industry currently is based on decentralized production activity using energy intensive, resource depleting and highly polluting technologies. Recently, Dr. Ashok Ghosh, Bihar State Chairman, Control Board Pollution (BSPCB), also raised the concern of top soil loss due to traditional brick making practices. In order to ensure that state's economic growth is not at the cost of environmental and public health, it is extremely important to take initiatives to promote cleaner brick production technologies and waste management.
According to Dr. Soumen
Maity, Vice President, Maity, Development Alternatives Group, "In the given situation, encouraging the production and the usage of fly ash bricks in Bihar is an opportunity for productive utilization of waste from thermal power plants while reducing the emission intensity of the brick production and providing decent jobs to local community. A Fly Ash Brick Quality Rating System implemented in selected districts of Bihar has shown that

fly ash brick manufacturers are producing good quality bricks as per Indian Standard". He also added that "some of the aspects of fly ash bricks are better than red bricks such as reducing the indoor temperatures and reduced use of mortar during construction. Hence fly ash bricks are not only eco-friendly, but also reduces cost of construction." Fly Ash production in Bihar and its benefits Bihar has 4 thermal power plants that produce an estimated 10.6 million tons of fly ash every year and this is expected to increase to 22.57million tonnes by the year 2020. There is enough fly ash available to produce about 7000 million bricks per year.

आज समाज

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डेवलपमेंट अल्टरनेटिका

की बिहार में ईट उद्योग को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए पहल

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने बिहार में पारंपरिक ईंट बनाने की प्रथाओं के कारण शीर्ष मिटटी के नुकसान पर अपनी चिंता व्यक्त की है और इससे जुडी हुई विभिन्न चुनौतियों पर काम करने के लिए डेवलपमेंट अल्टरनेटिका, एक गैर-लाभकारी संगठन के साथ मिलकर सक्रिय कि राज्य की आर्थिक वृद्धि पर्यावरण प्रयास कर रहा है।

बिहार में ईंट उद्योग कर्जा गहन, संसाधन घटाने और अत्यधिक प्रदूषण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके विकेन्द्रीकृत उत्पादन गतिविधि पर आधारित है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) के अध्यक्ष हाँ अशोक घोष ने पारंपरिक इंट बनाने तरीकों और धिहार की अर्थव्यवस्था पर इसका समग्र प्रभाव होने के कारण शीर्ष मिट्टी के नुकसान की चिंता उठाई है। उन्होंने जोर दिया कि विहार मुख्य रूप से कृषि राज्य है और इंट उत्पादन और सड़क निर्माण के कारण हर साल 10000 हेक्टेयर शीर्ष मिट्टी खो जाती है। नतीजतन, कृषि उत्पादन में काफी हद तक बाधा आ जाएगी और राज्य की खाद्य उत्पादन क्षमता को चुनौती देगी। लाल ईंट उद्योग में खाद्य सुरक्षा, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य चिंताओं और बिहार की समग्र स्थित

बिहार में बारंपरिक लाल ईंट उद्योग में खाद्य सुरक्षा, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य चिंताओं और बिहार के समग्र राज्य की आर्थिक वृद्धि और कल्याण सहित कई चुनौतियां हैं और इसलिए निर्माण क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए

के आर्थिक विकास सहित कई चुनौतियां हैं और इसलिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।

यह सुनिश्चित करने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य की लागत पर नहीं है, पर्यावरण अनुकूल ईंट उत्पादन पौद्योगिकियों और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए पहल करना बेहद महत्वपूर्ण है। इस संबंध में व्यवस्थित कार्रवाई और फॉलो-अप करने के मामले में बिहार अग्रणी रहा हैय टास्क फोर्स की स्थापना फ्लाई एश गणवत्ता रेटिंग सिस्टम, ग्रीन एंटरप्राइज मेला, राज्य परामर्श, क्षमता विकास, प्रौद्योगिकी सुधार, नई तकनीक और जागरूकता सहित कई पहल की गई हैं। ग्लीबल थिंक टैंक डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज क्लीनर ईंट उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार के साथ काम कर रहा है। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज समूह के वाईस प्रेसिडेंट, डॉ सौमेन माईटी के अनुसार 'बिहार में 153 फ्लाई ऐश ईंट उद्यम हैं। उन्होंने संकेत दिया कि नीति पर्यावरण बिहार में अनुकूल है, लेकिन कार्यान्वयन

को आगे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उन्होंने रेखांकित किया, फ्लाई ऐश ईंट उपयोग सहित मजबूत निगरानी प्रणाली की आवश्यकताय फ्लाई ऐश ईंट बनाने लाने में मदद करेगा। इकाइयों के लिए रेत कोटाय ओपीसी सीमेंट उपलब्धता को हल करनाय जिला क्लस्टरिंग को पोत्साहित करना य फ्लाई ऐश ईंटों के प्रचार और जागरूकता के लिए प्रचारय

डॉ के. विजया लक्ष्मी. उपाध्यक्ष, डेवलपमेंट अल्टरनेटिब्ज, का कहना है की फ्लाई ऐश ईटें सबसे अधिक 'अनुकूल सामग्री' है, क्योंकि यह थर्मल पावर प्लांट्स के अपशिष्ट का उपयोग करती है, शीर्ष मिट्टी पर बोझ कम करती है, और जीएचजी उत्सर्जन भी कम कर देती है। हालांकि, उन्होंने प्रकाश डाला कि पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक लाभ लाने के लिए केवल टिकाक उत्पादन पर्याप्त नहीं हो सकता है, उपभोग पैटर्न में परिवर्तन एक सतत भविष्य के लिए समान रूप से

आवश्यक है। तदनुसार, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक आंदोलन उपभोग पैटर्न में बदलाव

बिहार में 4 थर्मल पावर प्लांट हैं जो हर साल अनुमानित 10.6 फ्लाई ऐश ईंट बनाने इकाइयों के मिलियन टन फ्लाई ऐश का उत्पादन करते हैं और 2020 तक यह 22.57 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। प्रति वर्ष 7000 मिलियन इंटों और फ्लाई ऐश ईंटों की उपलब्धता के उत्पादन के लिए पर्याप्त फ्लाई और गुणवत्ता पर जानकारी में अंतर ऐश उपलब्ध है। फ्लाई ऐश को कम करने की आवश्यकता है।' प्रौद्योगिकी के लाभ हैंरू (१.) यह उपजाक मिट्टी को संरक्षित करता हैय प्रति 10000 फ्लाई ऐश ईंट बचाता है 30 टन मिटटी. (2.) यह फ्लाई पेश और अन्य अपशिष्ठ का उपयोग करता हैय 15 टन कचरा प्रति 10000 पलाई ऐश ईंट बनाने में उपयोग किया जाता है. (3.) ळतममद यह ग्रीनहाउस गैस उत्पादन को कम करता हैय करीब 100 टन फ्लाई ऐश ईंट बचाता है लगभग ७ टन कार्बन कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करता हैय प्रति 10000 फ्लाई ऐश ईंट से लगभग 2 टन

बिहार में फ्लाई ऐश इंट निर्माण और मांग में तेजी लाने के लिए हाल ही में कई कदम उठाए गए हैं-

एक फ्लाई ऐश ईंट गुणवत्ता रेटिंग सिस्टम (एफएबीक्युआरएस) को डिजाइन किया गया है।

बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिहार विभाग द्वारा एक अधिमान्य खरीट नीति स्थापित की गई है जो सभी सरकारी निर्माण को 100. फ्लाई ऐश ईंटों का उपयोग करने के लिए अनिवार्य है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) ने श्वृहाइटश श्रेणी में फ्लाई ऐश ईंटें लगाई हैं, जहां फ्लाई ऐश ईंट इकाइयों को बोर्ड से प्रदेषण नियंत्रण सहमति लेने से छूट दी गई है।

बीएसपीसीबी में हाल ही में एक राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन बिहार में निर्माण क्षेत्र को और अधिक हरे और समावेशी क्षेत्र में बदलने के दृष्टिकोण पर आयोजित किया गया ।

इस साल की शुरूआत में पटना में एक श्र्मीन एंटरप्राइज मेलाश उद्यम आयोजित किया गया था।

बिहार के 4 जिलों (सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, नालंदा) में डीए द्वारा फ्लाई ऐश ईटों पर जिला स्तर की जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं।